



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 3 अप्रैल, 2007 / 13 चैत्र, 1929

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171 004, 2 अप्रैल, 2007

संख्या वि० स०-विधायन-गवर्नमेंट बिल/1-17/2007.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्यसंचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2007 (2007 का विधेयक संख्यांक-4) जो आज दिनांक 2 अप्रैल, 2007 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

जे० आर० गाजटा,
सचिव।

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन)
विधेयक, 2007

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम ।
2. धारा 2 का संशोधन ।
3. धारा 3 का संशोधन ।
4. धारा 5 का संशोधन ।
5. धारा 18 का संशोधन ।
6. धारा 22 का संशोधन ।
7. धारा 23 का संशोधन ।

५ -

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2007

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम,
1984 (1984 का 18) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के अठारहवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित
रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संक्षिप्त नाम।
संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) अधिनियम, 2007 है।

2. हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, धारा 2 का
1984 का 18 1984 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में,— संशोधन।

(क) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(च) “हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था” से धार्मिक उद्देश्य से सार्वजनिक
प्रयोजन के लिए स्थापित मठ, मन्दिर, समाधि, समाधि, डेरा और उससे
सम्बद्ध विन्यास या विनिर्दिष्ट विन्यास अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत
निम्नलिखित है,—

- (i) किसी मठ, मन्दिर, समाधि, समाधि या डेरा की या
उसमें पूजा के लिए, उसके अनुरक्षण या सुधार
के लिए या उसमें परिवर्धन के लिए उनसे
सम्बन्धित किसी सेवा या पूर्त कार्य के लिए दी
गई या विन्यास की गई सम्पूर्ण जंगम या स्थावर
सम्पत्ति;
- (ii) मठ, मन्दिर, समाधि, समाधि या डेरा में स्थापित
मूर्तियां, कपड़े, आभूषण और अलंकरण आदि की
अन्य वस्तुएं ; और

- (iii) राज्य सरकार के सीधे नियन्त्रणाधीन धार्मिक संस्था; किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे निजी धार्मिक मठ, मन्दिर, समाध, समाधि या डेरा सम्मिलित नहीं है जिनमें जनता हितबद्ध नहीं है :

परन्तु किसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था में किसी तीर्थयात्री या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई चढ़ावा, चाहे वस्तु रूप में या नकद में हो, ऐसी धार्मिक संस्था की सम्पत्ति समझी जाएगी; और

- (ख) खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(ज) “पुजारी” के अन्तर्गत पाण्डा या न्यासी के रूप में पद धारण करने वाले आनुवंशिक न्यासियों से अन्यथा पूजा या अन्य धार्मिक कर्मकाण्ड करने के लिए आयुक्त द्वारा नियुक्त व्यक्ति हैं ; ”।

धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

- (क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(1—क) राज्य सरकार का प्रधान सचिव या सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति) मुख्य आयुक्त (मन्दिर) होगा।” और

P

पं. 11

- (ख) उपधारा (3) के अन्त में चिन्ह “।”, के स्थान पर “और मन्दिर न्यासों के कर्मचारियों के भर्ती और प्रोन्नति नियम तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जैसी मुख्य आयुक्त (मन्दिर) द्वारा अधिसूचित की जाएं।” शब्द, कोष्ठक और चिन्ह रखे जाएंगे।

धारा 5 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

- “(3) धारा 20 के अध्यक्षीन आयुक्त, यदि उचित समझे, मन्दिर के अधीक्षण और नियन्त्रण के लिए न्यासियों की प्रबन्ध समिति का गठन कर सकेगा।
- (4) किसी भी मन्दिर में भर्ती, यान का क्रय या नया निर्माण कार्य मुख्य आयुक्त (मन्दिर) के पूर्व अनुमोदन के अध्यक्षीन होगा।
- (5) आयुक्त प्रत्येक स्कीम में पचास हजार रुपए तक के लिए वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा और जिन स्कीमों में पचास हजार रुपए से

अधिक का व्यय अन्तर्वलित है उन्हें मुख्य आयुक्त (मन्दिर) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और ऐसी स्कीमें निदेशक, भाषा और संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा मुख्य आयुक्त (मन्दिर) को अग्रेषित की जाएंगी :

परन्तु इस उपधारा के अधीन नियत अधिकतम सीमा मन्दिर, न्यासों, समितियों या न्यासों या समितियों के नियन्त्रणाधीन अन्य संस्थाओं के कर्मचारिवृन्द के वेतन या मानदेय के लिए लागू नहीं होगी।”।

5. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित धारा 18 का उपधाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:— संशोधन।

- “(5) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त पांच आनुवंशिक, पांच अन-आनुवंशिक और दस शासकीय न्यासियों से अधिक नियुक्त नहीं करेगा जो न्यास का गठन करेंगे।
- (6) न्यास की बैठक के लिए गणपूर्ति न्यासियों की कुल संख्या के दो तिहाई से होगी और प्रत्येक बैठक में तीन आनुवंशिक न्यासियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।”।

6. मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (5)के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा धारा 22 का अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— संशोधन।

- “(6) लेखापरीक्षा और लेखा विवरणिका सहित, वार्षिक बजट अनुमोदन के लिए प्रबन्ध समिति के समक्ष रखा जाएगा।”।

7. मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा धारा 23 का अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— संशोधन।

- “(4) मन्दिर न्यासों की आन्तरिक लेखा परीक्षा भाषा एवं संस्कृति विभाग के अनुभाग अधिकारी (एस0ए0एस0) द्वारा संचालित की जाएगी।”।

**THE HIMACHAL PRADESH HINDU PUBLIC RELIGIOUS
INSTITUTIONS AND CHARITABLE ENDOWMENTS (AMENDMENT)
BILL, 2007**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

CLAUSES:

1. Short title.
2. Amendment of section 2.
3. Amendment of section 3.
4. Amendment of section 5.
5. Amendment of section 18.
6. Amendment of section 22.
7. Amendment of section 23.

**THE HIMACHAL PRADESH HINDU PUBLIC RELIGIOUS
INSTITUTIONS AND CHARITABLE ENDOWMENTS (AMENDMENT)
BILL, 2007**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 (Act No. 18 of 1984).

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments (Amendment) Act, 2007. Short title.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 (hereinafter referred to as the "principal Act")— Amendment of section 2.

(a) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:—

“(f) “Hindu public religious institution” means a math, temple, smadh, smadhi, dera and endowment attached thereto or a specified endowment, established with a religious object for a public purpose and includes,—

- (i) all property movable or immovable belonging to or given or endowed for worship in, maintenance or improvement of, additions to, a math, temple, smadh, smadhi or dera for the performance of any service of charity connected therewith;
- (ii) the idols installed in the math, temple, smadh, smadhi or dera, cloths, ornaments and things, for decoration etc.; and
- (iii) religious institution under the direct control of the State Government; but does not include such private religious math, temple, smadh, smadhi or dera, in which the public are not interested:

Provided that any offering, whether in kind or in cash, made by any pilgrim or by any other person in any Hindu public religious institution shall be deemed to be the property of such religious institution;” and

(b) for clause (j), the following clause shall be substituted, namely:—

“(j) “pujari” includes a panda or a person appointed by the Commissioner for performing puja or other rituals, other than hereditary trustees holding office as trustee;”

Amendment
of section 3.

3. In section 3 of the principal Act—

(a) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(1-A) The Principal Secretary or Secretary (Language Arts and Culture) to the State Government shall be the Chief Commissioner (Temple).”; and

(b) in sub-section (3), at the end, for the sign “.”, the words, brackets and sign “and the Recruitment and Promotion Rules and other conditions of service of the temple trusts employees shall be such as may be notified by the Chief Commissioner (Temple).” shall be substituted.

Amendment
of section 5.

4. In section 5 of the principal Act, after sub-section (2), the following sub-sections shall be inserted, namely:—

“(3) Subject to section 20, the Commissioner may constitute a Managing Committee of the trustees for superintendence and control of the temple, if deems proper.

(4) The recruitment, purchase of vehicle or new construction work in any temple, shall be subject to the prior approval of the Chief Commissioner (Temple).

(5) The Commissioner shall exercise the financial powers upto fifty thousand rupees in each Scheme, and the Schemes involving expenditure exceeding fifty thousand rupees, shall be approved by the Chief Commissioner (Temple) and such Schemes shall be forwarded by the Director, Department of Language and Culture, Himachal Pradesh to the Chief Commissioner (Temple):

Provided that the maximum limit fixed under this sub-section shall not apply in release of salaries or honorarium of the staff of

the temple, trusts, committees or other institutions under the control of trusts or committees.

5. In section 18 of the principal Act, after sub-section (4), the following sub-sections shall be inserted, namely:—

Amendment
of section
18.

“(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Commissioner shall appoint not exceeding, five hereditary, five non-hereditary and ten official trustees which shall constitute a trust.

(6) The quorum for the meeting of the trust shall be two third of the total number of trustees and in each meeting presence of three hereditary trustees shall be mandatory.”.

6. In section 22 of the principal Act, after sub-section (5), the following sub-section shall be inserted, namely:—

Amendment
of section
22.

“(6) The annual budget including audit and accounts statement shall be placed before the Management Committee for its approval.”.

7. In section 23 of the principal Act, after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:—

Amendment
of section
23.

“(4) The internal audit of the temple trusts shall be conducted by the Section Officer (SAS) of the Language & Culture Department.”.

